



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 2009/ज्येष्ठ 4, 1931

No. 192]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 2009/JYAISTHA 4, 1931

खान मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 21 मई, 2009

सं. 20/02/2009-खान-II.—भारत सरकार ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने तथा संगठन के प्रौद्योगिकीय एवं जनशक्ति संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उत्पन्न हो रही चुनौतियों का सामना करने की इसकी क्षमता का आकलन करने के लिए, 7 जनवरी, 2008 के संकल्प संख्या 11(39)-2007-खान-I के तहत एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच पी सी) का गठन किया था। उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, जी एस आई के लिए भावी दिशा (विजन) तथा इसके प्रचालनों के लिए एक चार्टर निर्धारित करते हुए अपनी रिपोर्ट 31 मार्च, 2009 को सरकार को प्रस्तुत की थी। सरकार ने, मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद एच पी सी की इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और तदनुसार जी एस आई की भावी दिशा (विजन) तथा इसके प्रचालनों का चार्टर एतदप्रश्चात् इस संकल्प के अनुबंध-I तथा II में यथा निर्धारित के अनुसार होगा।

शान्ता शीला नायर, सचिव

अनुबंध-I

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की भावी दिशा (विजन)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण निम्न की आकांक्षा करेगा :

- मौलिक तथा अनुप्रयुक्त भूविज्ञान वाली एक विश्व स्तरीय संस्था के तौर पर विकास करना और हमेशा नवीनतम प्रौद्योगिकियों तथा कार्य पद्धतियों को अद्यतन बनाए रखना।
- नेतृत्व तथा सहयोगात्मक साझेदारी के माध्यम से सुसम्बद्ध राष्ट्रीय भूवैज्ञानिकों के समूह का सृजन करना।
- कार्य में विशेषज्ञता अर्जित करना तथा प्रदान करना और नीति निर्माताओं तथा जनता द्वारा सुविज्ञ निर्णय लेने को सुकर बनाने

के लिए भूवैज्ञानिक सूचना का व्यापक तौर पर प्रसार करना और सतत सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भूवैज्ञानिक सूचना के उपयोग को समर्थ बनाना।

अनुबंध-II

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रचालनों का चार्टर

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की भावी दिशा (विजन) तथा भूवैज्ञानिक क्षेत्र में प्रमुख अवसरों एवं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, जीएसआई निम्नलिखित कार्य करेगा :

- विशेष रूप से नीतिगत, व्यापिक, आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं से संबंधित निर्णय लेने के लिए वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष और अद्यतन भूवैज्ञानिक सुविज्ञता और सभी प्रकार की भूवैज्ञानिक सूचना प्रदान करना व इसे सुसाध्य बनाना।
- भूभौतिकीय, भूरासायनिक और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों सहित अद्यतन और सबसे किफायती तकनीक और कार्यप्रणालियों का उपयोग करके भारत की सतह और अंतःसतह तथा इसके अपतटीय क्षेत्रों के भूविज्ञान एवं भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का क्रमबद्ध प्रलेखन।
- स्थानिक डाटाबेसों (जिसमें सुदूर संवेदन के माध्यम से उपार्जित डाटाबेस शामिल हैं) की निरंतर अमिवृद्धि, प्रबंधन समन्वय और उपयोग के जरिए सर्वेक्षण और मानचित्रण में जीएसआई की प्रमुख सक्षमता को विकसित करना एवं इसमें सतत रूप से वृद्धि करना और इस प्रयोजनार्थ 'मण्डार' अथवा 'क्लीयरिंग हाउस' के रूप में कार्य करना तथा भूवैज्ञानिक सूचना और स्थानिक डाटा के प्रचार-प्रसार के लिए भूसूचना क्षेत्र के अन्य हिस्सेदारों के साथ सहयोग और गठबंधन के माध्यम से नई एवं उभरती हुई कम्प्यूटर-आधारित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना।

- देश के लिए खनिज, ऊर्जा और जल संसाधनों का गवेषण (जमीनी, हवाई, उपग्रही और समुद्री सर्वेक्षणों के माध्यम से) और वैज्ञानिक रूप से आकलन करना और सक्रिय सूचना प्रचार-प्रसार के जरिए इनके इष्टतम गवेषण को सुसाध्य बनाना।
- भूविज्ञान के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका को कायम रखना तथा केन्द्र, राज्य और अन्य संस्थानों के साथ साझेदारियां विकसित करना ताकि जीएसआई की भावी दिशा (विजन) और इस चार्टर के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूविज्ञान के क्षेत्र में वर्धित कार्यकारी योग्यता और क्षमता सृजित करने में सहायता मिल सके।
- देश के प्राकृतिक संसाधनों जिसमें पानी भी शामिल है, के सतत प्रबंधन में मदद करने के लिए भूविज्ञान से संबंधित सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारों के साथ भूवैज्ञानिक कार्यकलापों का समन्वय करना।
- बहुविषयक और मौलिक भूवैज्ञानिक अनुसंधान और अध्ययन (भूतकनीकी अन्वेषणों, भौतिकीय, रासायनिक और जैविक अपदा संबंधी भू-अन्वेषणों, जलवायु परिवर्तन संबंधी भू-अध्ययनों, पुरा-भू-अध्ययनों आदि सहित) करना और इस प्रयोजनार्थ राज्यों और केन्द्र के अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारियां करना।
- विवर्तनीकी (टेक्टॉनिक्स), वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित अध्ययनों और ध्रुवीय अध्ययनों सहित पृथ्वी और इसकी पारिस्थितिकी-प्रणालियों और इसके भूविज्ञान के बारे में अपनी समझ को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना।
- विद्यार्थियों, अनुसंधानकर्ताओं और जनता के उपयोग के लिए संग्रहालयों, स्मारकों और पार्कों, अभिलेखागारों, पुस्तकालयों तथा अन्य सुविधाओं के सृजन और प्रबंधन सहित प्रलेखन, प्रचार-प्रसार, अभिलेखन और शिक्षा के माध्यम से भूविज्ञान विषय को सामान्यतया प्रोत्साहित करना। उच्च गुणवत्ता वाली दृश्य-श्रव्य और मुद्रित सामग्री के उत्पादन और प्रचार-प्रसार के जरिए तथा इंटरनेट के माध्यम से विद्यालय और विश्वविद्यालय के स्तरों पर भूविज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष रूप से निरंतर प्रयास करना। इसके अतिरिक्त, भूवैज्ञानिक संकल्पनाओं को जनता के समक्ष लाने के लिए प्रदर्शनियों और विशेष समारोहों का आयोजन करना।

MINISTRY OF MINES RESOLUTION

New Delhi, the 21st May, 2009

No. 20/02/2009-M. II.—The Government of India vide Resolution No. 11(39)/2007-M. I, dated 7th January, 2008 had set up a High Powered Committee (HPC) to review the functioning of the Geological Survey of India (GSI) and assess its capacity to meet the emerging challenges taking into account the Organization's technological and manpower resources. The High Powered Committee submitted its report to the Government on 31st March,

2009, *inter alia* setting out a Vision for the GSI and a Charter for its operations. The Government after careful consideration of the matter has accepted these recommendations of the HPC and accordingly the Vision for GSI and its Charter of Operations shall be as is set out hereinafter in the Annexure I and II to this Resolution,

SANTHA SHEELA NAIR, Secy.

ANNEXURE-I

VISION FOR

THE GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

The Geological Survey of India shall aspire to :

- develop into a world class institution for fundamental as well as applied geoscience, always keeping up with the latest technologies and methodologies;
- create a close-knit national geoscientific community through leadership and collaborative partnerships; and
- acquire and provide expertise and widely disseminate geoscientific information to facilitate informed decision-making by policy-makers and public and enable use of geoscientific information for sustainable socio-economic development.

ANNEXURE-II

CHARTER OF OPERATIONS OF THE GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Having regard to the Vision for the Geological Survey of India (GSI), and the major opportunities and challenges in the geoscientific sector, the GSI shall :

- Enable and facilitate the providing of objective, impartial and up-to-date geological expertise and geoscientific information of all kinds, particularly for decision-making for policy, commercial, economic and societal needs.
- Systematically document the geology and geological processes of the surface and sub-surface of India and its offshore areas using the latest and most cost-effective techniques and methodologies, including geophysical, geochemical and geological surveys.
- Develop and continually enhance GSI's core competence in survey and mapping through continued accretion, management, co-ordination and utilization of spatial databases (including those acquired through remote sensing) and function as a 'Repository' or 'clearing house' for the purpose and use new and emerging computer-based technologies for dissemination of geoscientific information and spatial data, through cooperation and collaboration with other stakeholders in the Geoinformatics sector.
- Explore (through ground, airborne, satellite, and marine surveys) and scientifically assess mineral, energy and water resources for the country and facilitate their optimal exploration through proactive information dissemination.

- Maintain a leadership role in the geological field and develop partnerships with Central, State and other institutions, to help create enhanced executional capability and capacity in the field of geology in furtherance of GSI's Vision and the objectives of this Charter.
- Coordinate geoscientific activities with stakeholders in all sectors related to geoscience in order to help sustainably manage the country's natural resources, including water.
- Conduct multi-disciplinary as well as fundamental Geoscientific research and studies (including geotechnical investigations, physical, chemical and biological hazard geoinvestigations, climate change geostudies, paleogeostudies etc.), and foster partnerships with State and Central research and academic institutions for the purpose.
- Actively participate in international collaborative projects to improve our understanding of the earth and its ecosystems and its geology, including studies related to tectonics, global warming and climate change, and Polar studies.
- Generally advance the cause of the geoscience by documentation, propagation, archiving and education, including creation and management of museums, monuments and parks, archives, libraries and other facilities for use of students, researchers and the public. In particular constantly endeavour to popularize Geoscience at school and university levels through production and dissemination high quality audio-visual and printed material, and through the medium of the Internet. Also hold exhibitions and special events to bring geoscientific concepts before the public.